

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 120 राँची, शनिवार,

21 माघ, 1938 (श॰)

11 फरवरी, 2017 (ई॰)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

31 जनवरी, 2017

विषय:- खूंटी नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धित के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि रु॰ 9667.24 लाख (रू॰ छियानवे करोड़ सडसठ लाख चौबीस हजार मात्र) एवं SBM के केंद्र मद से रु॰435.32 लाख (रू॰ चार करोड़ पैंतीस लाख बत्तीस हजार मात्र) तथा राज्य योजना मद 20 वर्षों में कुल राशि रु॰ 4926.83 लाख (रू॰ उनचास करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार) अर्थात कुल रु॰ 5362.15 लाख (रू॰ तिरपन करोड़ बासठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

संख्या- SUDA/SBM/SWM/23-2015-880-- 74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । अतः नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

- 2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तार्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है । इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है ।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी MSW Rule 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेत् बल दिया जा रहा है ।
- 4. OSP प्रक्षेत्र, खूंटी नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है, जिसमें door to door collection, transportation, segregation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है | इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा प्रथम चरण की निविदा EPC Mode पर एवं दुसरे चरण की निविदा को लोक निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है। इस योजना का 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX पर आने वाले कुल व्यय का विस्तृत विवरण तालिका-1 में दर्ज है।
- 5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है I
- निकाय के पास 6.9 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु पर्याप्त है ।
- 7. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात **रु॰ 298.20 लाख** (रू॰ दो करोड़ अठानवे लाख बीस हजार मात्र) का व्यय किया जायेगा ।

तालिका – 1

Khunti Solid Waste Management - Fund Flow		
S. No.	Particular Particular	Amount in Rs. Lakh
1	Total Project Cost (=1.1+1.2+1.3)	9667.24
1.1	Capital Cost (CAPEX)	994.02
1.2	O & M Cost for 20 Yrs.	8544.00
1.3	Other Expenses (=1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	129.22
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	14.91
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	14.91
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	99.40
2	Total Income (= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	4006.89
2.1	by User Charges in O&M	2182.36
2.2	by Sale of Compost in O&M	1242.91
2.3	by Sale of Recyclable in O&M	568.43
2.4	by Scrap Sale in O&M	13.19

3	Central Share (=3.1+3.2+3.3)	435.32
3.1	Central Share for DPR preparation @ Rs. 12 per capita	4.36
3.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	347.91
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (= 1yrs.)	83.05
4	Investment of PPP Operator	298.20
	Investment by private partner in CAPEX @ 30% (PPP mode)	298.20
5	Total Grant Required from State (= 5.1+5.2+5.3)	4926.83
5.1	In CAPEX	347.91
5.2	In O&M in 20 years	4454.06
5.3	In Other	124.86

- 8. केन्द्रांश से कुल राशि रू॰ 435.32 लाख (रू॰ चार करोड़ पैंतीस लाख बत्तीस हजार मात्र) SBM योजना के तहत Mission Period, 2 Oct. 2019 तक @ 35% CAPEX एवं OPEX मद तथा @ 20% एवं Rs. 12 प्रति व्यक्ति DPR बनाने हेत् दिया जाना है ।
- 9. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किये जाने का प्रस्ताव है ।
- 10. SBM के राज्य योजना मद से कुल राशि रू॰ 4926.83 लाख (रू॰ उनचास करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार) दिया जाना है ।
- 11. योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन मद से किया जायेगा ।

12. तालिका- 2

S. No.	Particulars	Amount in Rs. Lakhs
1.0	Total Project Cost	9667.24
2.0	Central Government Share	435.32
3.0	Fund from PP partner	298.20
4.0	Total Income from Project	4006.89
5.0	Total State Government Share $(1.0 - 2.0 - 3.0)$	4926.83

- 13. योजना की निविदा प्रक्रिया, दो अलग- अलग चरणों द्वारा पूर्ण की जाएगी :
 - क. प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage and transfer हेतु सयंत्र एवं वाहनों का क्रय Item rate basis के द्वारा किया जायेगा, जिस पर कुल व्यय रू॰ 126.77 लाख (रू॰ एक करोड़ छब्बीस लाख सतत्तर हजार) होगी।
 - ख. दूसरी निविदा PPP Mode पर आमंत्रित किया जाना है, जिसके तहत processing plant तथा landfill site का निर्माण, मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा । निविदा में Capital cost item rate basis पर तथा O&M cost Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा ।
- 14. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य में खूंटी नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की कुल लागत राशि रू॰ 9667.24 लाख (रू॰ छियानवे करोड़ सडसठ लाख चौबीस हजार मात्र)

एवं SBM के केंद्र मद से राशि रू॰ 435.32 लाख (रू॰ चार करोड़ पैंतीस लाख बत्तीस हजार मात्र) तथा राज्य योजना मद 20 वर्षों में कुल राशि रू॰ 4926.83 लाख (रू॰ उनचास करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार) निकाय को 20 वर्षों में अनुदान देने एवं कार्य करने हेतु, मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह, सरकार के प्रधान सचिव ।
